

मूल निवेश कंपनी, लिमिटेड

बनाम

आयकर आयुक्त बम्बई

(भगवती, एस. के. दास और जे. एल. कपूर जे.जे)

आय-कर-उच्च न्यायालय का संदर्भ-कानून निवेश कंपनी के प्रश्न-विक्रेता या निवेशक-कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न-पाए गए तथ्यों का कानूनी प्रभाव, कानून का प्रश्न है।

अपीलार्थी कंपनी को एक निवेश कंपनी के रूप में निगमित किया गया था जिसने अपने संगठन के ज्ञापन द्वारा इसे सक्षम बनाया, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेश और संपत्तियों में सौदा करना। आयकर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए अपीलार्थी ने दावा किया कि विचाराधीन निर्धारण वर्ष के लिए उसे एक निवेशक के रूप में माना जाएगा न कि इस आधार पर कि वह शेयरों, प्रतिभूतियों या संपत्तियों की खरीद या बिक्री में कोई व्यवसाय नहीं करता है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि कंपनी के संगठन के ज्ञापन और अतीत में किए गए उसके अपने दावों के अनुसार, इसे निवेश और संपत्तियों में एक व्यापारी के रूप में माना जाना चाहिए और शेयरों और संपत्तियों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली इसकी आय पर व्यावसायिक लाभ के रूप में कर लगाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालयों को संदर्भित करने के लिए अपीलार्थी के आवेदनों को इस आधार

पर खारिज कर दिया गया कि न्यायाधिकरण के आदेश से कानून का कोई सवाल नहीं उठा।

अभिनिर्धारित किया कि यह प्रश्न कि क्या अपीलार्थी का व्यवसाय शेयरों और संपत्तियों में लेनदेन करने या निवेश करने के बराबर है, कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है और यह कि न्यायाधिकरण द्वारा पाए गए तथ्यों का कानूनी प्रभाव जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी एक व्यापारी या निवेशक के रूप में माना जा सकता है, यह कानून का सवाल है। तदनुसार, उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया और न्यायाधिकरण को एक मामला बताने का निर्देश देने के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेज दिया गया।

(1) (1944) 12 आई. टी. आर 393

मीनाक्षी मिल्स, मद्रुरै बनाम। आयकर आयुक्त, मद्रास, (1956) एस. सी. आर. 691 ने आवेदन किया।

मामला कानून की समीक्षा की गई।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 1954 का 153

निर्णय से विशेष अनुमति द्वारा अपील और बंबई उच्च न्यायालय का 15 जनवरी, 1952 का आदेश

आय न्यायालय-1951 का कर आवेदन सं. 54 ।

आर. जे. कोलाह, जे. बी. दादाचंजी, एस. एन. एंडली और रामेश्वर नाथ, अपीलार्थी की ओर से।

सी. के. डाफ्टरी, सॉलिसिटर-भारत के महाधिवक्ता, जी. एन. जोशी और आर. एच. डेबर, प्रतिवादी के लिए।

22 मई 1957 न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया ।

कपूर जे. - यह निर्धारिती द्वारा की गई एक अपील है; विशेष अवकाश और निर्णय के लिए सवाल यह है कि क्या कानून के प्रश्न, यदि कोई हों, अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न होते हैं ।

अपील को जन्म देने/उठाने वाले तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता कंपनी का गठन एक निवेश कंपनी के तौर पर 29 जुलाई, 1924 को किया गया था। । संघ के ज्ञापन का सी. एल. III में स्थापित है और विशेष रूप से उप-सी. एल. में 1, 2, 15 और 16 में से वह खंड समीक्षाधीन मूल्यांकन वर्ष हैं - वर्ष 1943-44 से 1948-49 तक, 1947-48 को छोड़कर । याचिकाकर्ता कंपनी बॉम्बे अपनी परिसंपत्तियों से निपटती थी, जो इस प्रकार है:

" याचिकाकर्ता कंपनी ने इस दौरान 1 जुलाई 1925 से 30 जून 1928 तक 1,86,47,789 / - मूल्य के शेयर खरीदें जिसमें ससून ग्रुप ऑफ मिल्स के बड़े हिस्से के शेयर शामिल हैं। 30 जून 1929 को समाप्ति वर्ष के दौरान

याचिकाकर्ता कंपनी ने लॉयल मिल्स लिमिटेड और हैमिल्टन स्टूडियो लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली दो कंपनियों को बढ़ावा दिया और उनके सभी शेयर जिनका मूल्य 10 लाख रुपये है पर अधिग्रहण किया । वर्ष 1930 में याचिकाकर्ता कंपनी ने इसके शेयर 133,930 रुपये में खरीदे । 9 वर्ष के अंतराल के दौरान 1 जुलाई 1930 से 30 जुलाई 1939 तक कोई खरीद नहीं की गई थी । सिवाय लॉयल मिल्स लिमिटेड, के कुछ शेयरों को छोड़कर जो ई. डी. ससून एंड कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों से लिया गया, जो सेवा से सेवानिवृत्त हुए। 30 जून 1940 को समाप्त हुए वर्ष में अपोलो मिल्स लिमिटेड की पुनर्निर्माण योजना हुई, जिसके तहत अपोलो मिल्स लिमिटेड में याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा रखे गए डिबेंचरों को भुनाया गया और आय को अपोलो मिल्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए शेयरों के नए निर्गम में पुनः निवेश किया गया। याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा 30 जून 1941 को समाप्त वर्ष के दौरान रु। 2,000 / - लॉयल मिल्स लिमिटेड के शेयरों का मूल्य था, जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से लिया गया था, 30 जून 1943 को समाप्त हुए वर्ष में याचिकाकर्ता कंपनी ने डेविड मिल्स

कंपनी लिमिटेड, द एसोसिएटेड बिल्डिंग कंपनी के शेयरों से रु 56,700 / इसके बाद इस तारीख तक 34,954 रुपये मूल्य की खरीद को छोड़कर कोई खरीद नहीं हुई। इस दौरान वर्ष 30 जून 1946 को समाप्त हुआ।”

बिक्री पैरा 3 (बी) में निहित है जो हो सकती है - उद्धृत किया गया

" याचिकाकर्ता द्वारा की गई खरीद के संबंध में कंपनी जैसा कि ऊपर बताया गया है कोई उल्लेखनीय बिक्री नहीं हुई, 29 जुलाई, 1924 की अवधि के दौरान बनाए गए शेयरों की संख्या वर्ष 30 जून 1942 तक, में की गई बिक्री समाप्त हो गई 30 जून 1929 का मूल्य 1,29,333 रु शामिल हैं। 45,000 रुपये मूल्य के शेयर लॉयल मिल्स में लिमिटेड, कर्मचारियों और शेयरों के सदस्यों को बेचा गया 83,833 रुपये मूल्य का स्टर्लिंग का प्रतिनिधित्व करना याचिकाकर्ता कंपनी के लेनदारों को सौंपे गए निवेशद्वारा लिए गए ऋण का आंशिक पुनर्भुगतान 30 जून, 1931 को समाप्त हुए वर्ष में उनके शेयरों से 7,48,356 रुपये मूल्य का उन्हें सौंप दिया गया । लेनदार अपने द्वारा दिए गए ऋण के भुगतान में कं. लिमिटेड ने प्रबंध एजेंसियों को छोड़ना शुरू कर दिया । उनकी एजेंसी के तहत विभिन्न

मिलों और शेयरों का सासून समूह में याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा आयोजित मिल्स को संबंधित मिल्स एजेंसियों के खरीदार को सौंप दिया गया था ।"

यह अधिग्रहण और निपटान का इतिहास बताता है शेयरों की संख्या और यह भी कि विभिन्न लेनदेन में कैसे प्रवेश किया गया और क्यों । 1940 से पहले निर्धारिती कंपनी ने हर साल के रूप में माने जाने का दावा किया कि लेकिन इस संबंध में निवेशों और संपत्तियों में एक व्यापारी को लगातार पीछे हटा दिया गया था और मूल्यांकन वर्ष 1939-40 तक निर्धारिती कंपनी का मूल्यांकन एक निवेशक होने के आधार पर किया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्यांकन वर्ष 1940-41 और उसके बाद के दो वर्षों 1941-42 और 1942-43 के लिए विभाग ने निर्धारिती कंपनी की याचिका को स्वीकार करते हुए इसे शेयरों, प्रतिभूतियों और अचल संपत्तियों में एक व्यापारी के रूप में माना और उस आधार पर इसका मूल्यांकन किया। इन वर्षों के लिए और आकलन वर्ष 1943-44 के लिए कंपनी ने उसी आधार पर अपना रिटर्न दिया। लेकिन वर्ष 1943-44 के लिए विवरणी दाखिल किए जाने के बाद निर्धारिती कंपनी ने अपना विवरणी वापस ले लिया और 7 मार्च, 1944 को एक संशोधित विवरणी दाखिल की, जिसमें तर्क दिया गया कि वह एक व्यापारी कंपनी नहीं बल्कि केवल एक निवेशक

थी। रिटर्न के साथ इसने 6 मार्च, 1944 को एक पत्र दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया था :

" कुल आय का रिटर्न जो जमा किया गया था कंपनी के 25 मई 1943 के पत्र के साथ था आयकर के फैसले के अनुरूप तैयार किया गया, 1940-41 में अधिकारी ने आकलन किया कि कंपनी निवेश में एक विक्रेता/व्यापारी कंपनी के रूप में मूल्यांकन किया जाना था।

तब से वह प्रतिफल केंद्रीय बोर्ड को सौंप दिया गया था राजस्व ने निर्णय लिया है कि कंपनी एक निवेश है अधिकार वाली कंपनी और तदनुसार एक संशोधन की धारा 22(1) के तहत कुल आय का प्रतिफल जिस पर भारतीय आयकर अधिनियम प्रस्तुत किया गया है 1943-44 का मूल्यांकन इसी पर आधारित हो सकता है स्पष्ट रूप से कंपनी के पास कोई विशेष प्रश्न नहीं हो सकता एक स्थिति अतिरिक्त लाभ कर के लिए और दूसरी स्थिति के लिए आयकर।"

यह भी तर्क दिया गया कि इसने कभी भी कोई कार्यवाही नहीं की शेयरों, प्रतिभूतियों या की खरीद या बिक्री में व्यवसाय संपत्तियों और इसलिए प्रार्थना की कि को ध्यान में रखते हुए इस पर केंद्रीय राजस्व बोर्ड

का आदेश जारी हुआ अतिरिक्त लाभ कर की धारा 26(1) के तहत आवेदन अधिनियम का आयकर उद्देश्य के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए निवेशक और डीलर के रूप में नहीं।

आयकर अधिकारी ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अपने व्यवसाय के व्यापार का कुल माल के रूप में निवेश जो उसने पिछले वर्ष के दौरान भी किया था। कंपनी ने अपीलीय सहायक आयुक्त से अपील की जिसे खारिज कर दिया गया और

आयकर अधिकारी के आदेश को बरकरार रखा गया ।

आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की, बॉम्बे जहाँ वही विवाद उठाए गए थे, लेकिन पीछे हटा दिए गए। न्यायाधिकरण ने कहा:

आयकर अधिकारी के आदेश बरकरार रखा गया । तब यह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, बंबई में अपील की, जहां वही विवाद उठाए गए थे जो टाल दिया गये थे। न्यायाधिकरण ने कहा:

" कंपनी ने पिछले सभी वर्षों में स्वयं यह मुद्दा उठाया था कि वह निवेश और संपत्तियों में एक व्यापारी कंपनी थी, इसलिए यह समझ पाना मुश्किल प्रतीत होता है कि कंपनी अब अपनी स्थिति क्यों बदलना चाहती है और आयकर अधिकारी उससे सौदा करना चाहते हैं, मानो वह शेयरों,

प्रतिभूतियों और अचल संपत्तियाँ में सौदा नहीं कर रहा थी

"।

न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि पहले के वर्षों में विक्रेता कंपनी निवेश में बिना किसी गलतफहमी के जब एक होने का दावा करता है क्योंकि यह तब हमेशा नुकसान होता था और वर्तमान विवाद इसलिए उठाया गया था क्योंकि इसने " संतोषजनक मुनाफे " बनाकर दिया था कहा:

" लेकिन हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंपनी के संगठन के ज्ञापन और उसके अपने अनुसार अतीत में किए गए सभी दावे, निर्धारिती कंपनी निवेश और संपत्तियों में एक व्यापारी कंपनी है और आय-कर अधिकारी द्वारा उसकी बिक्री पर उत्पन्न आय को आय-कर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर के लिए उत्तरदायी व्यावसायिक लाभ माना गया है।

इस प्रकार जिन आधारों पर निर्धारिती के खिलाफ मामले का निर्णय लिया गया था, वे थे (1) निर्धारिती ने अपने हानि या लाभ के खर्च के अनुसार व्यापारी या निवेशक होने का दावा किया और (2) संघ के ज्ञापन में निहित उद्देश्यों के कारण और एक व्यापारी के रूप में अतीत में किए गए अपने निवेशक होने के दावे के कारण निर्धारिती को एक व्यापारी नहीं माना जा सकता था।

इसके बाद कंपनी ने अपीलीय न्यायाधिकरण में आवेदन किया भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 66(1) के तहत की राय के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित प्रश्नों का संदर्भ लें:

"(1) चाहे तथ्यों पर हो या परिस्थितियों पर मामले में निर्धारिती कंपनी के साथ उचित व्यवहार किया जा सकता है निवेश और संपत्तियों के एक विक्रेता के रूप में; और

चाहे लाभ हो या हानि हो रही हो निर्धारिती कंपनी के शेयरों, प्रतिभूतियों और अचल संपत्तियों की बिक्री पर व्यावसायिक लाभ के रूप में कर लगाया जा सकता है।

इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि न्यायाधिकरण की राय में उसके आदेश से कानून का कोई सवाल नहीं उठा। इसमें कहा गया है:

" न्यायाधिकरण ने इस मुद्दे का फैसला केवल इसलिए नहीं किया क्योंकि कंपनी ने एसोसिएशन का ज्ञापन दिया था, कंपनी को निवेश और संपत्तियों में सौदा करने की शक्ति दी, लेकिन वास्तव में यह पाया गया कि कंपनी ने निवेश और संपत्तियों में सौदा किया था। पूरे समय और अतीत में भी जोर देकर कहा था कि यह निवेश और संपत्तियों में एक व्यापारी कंपनी थी।"

यह अपने अपीलीय आदेश में कही गई बात से कहीं अधिक था।

कर निर्धारिती कंपनी ने तब एक आवेदन किया. भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 66(2) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण से मामले को बताने और संदर्भित करने की मांग की गई है। यह उच्च न्यायालय में गया लेकिन इस आवेदन को खारिज कर दिया गया, और फिर कंपनी ने इस न्यायालय में अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त की।

कर निर्धारिती कंपनी के वकील का तर्क है कि कानून के प्रश्न न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न होते हैं क्योंकि न्यायाधिकरण ने वृत्तचित्र की अनदेखी की है, उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रासंगिक मामलों पर उसके निर्णय पर आधारित है, महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करने में विफल रहा है और यह मानते हुए खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता शुरू से ही एक व्यापारी था जो उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के विपरीत था।

आय-कर अधिनियम की धारा 66 (1) (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) में यह प्रावधान है कि कोई भी कर निर्धारिती अपीलीय न्यायाधिकरण से उसके अपीलीय आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न को उच्च न्यायालय को संदर्भित करने की अपेक्षा कर सकता है और यह अपीलीय न्यायाधिकरण का वैधानिक कर्तव्य है कि वह मामले के विवरण का मसौदा तैयार करे और ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाले

कानून के प्रश्न को उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करे, लेकिन प्राथमिक आवश्यकता यह है कि आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून का एक प्रश्न होना चाहिए। आदेश से उत्पन्न कानून का न्यायाधिकरण चाहिए

धारा के तहत अपेक्षित मामले को बताने से इनकार करें। 66(1) इस आधार पर अधिनियम का कि कानून का कोई प्रश्न नहीं है उठता है, उत्पन्न होता है, निर्धारिती को उच्च में आवेदन करने का अधिकार है न्यायाधिकरण चाहिए धारा 66(1) के तहत अपेक्षित मामले को बताने से इनकार करें। इस आधार पर न्यायाधिकरण को धारा 66(1) के तहत अपेक्षित मामले को बताने से इंकार चाहिए कि अधिनियम का कानून का कोई प्रश्न नहीं है उठता, निर्धारिती को उच्च-न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार है, जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरण से मामले को बताने की आवश्यकता होती है और इसे उच्च न्यायालय को संदर्भित करें लेकिन फिर भी आवश्यक है, आदेश से उत्पन्न होने वाला विचार कानून के प्रश्न का अस्तित्व है।

कानून का सवाल क्या है, इसके बीच एक रेखा खींचना और तथ्य का सवाल हमेशा आसान नहीं होता है। इस अंतर को परिभाषित करना मुश्किल है जिसने कई निर्णयों को जन्म दिया है, जिन पर इस स्तर पर चर्चा करना उपयोगी होगा।

स्टेनली वी. ग्रामोफोन और टाइपराइटर, लिमिटेड ('')

मास्टर ऑफ द रोल्ल्स ने इस प्रश्न पर चर्चा की जो निम्नलिखित है:

" यह निस्संदेह सच है कि, आयुक्तों ने एक तथ्य पाते हुए, यह इस अदालत के लिए उस निष्कर्ष पर सवाल उठाने के लिए खुला नहीं है जब तक कि इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत न हो। यदि, तथापि, आयुक्त उन साक्ष्यों का उल्लेख करते हैं जो उनके समक्ष थे, और उन्हें ऐसे साक्ष्य के आधार पर जोड़ते हैं उनका मानना है कि कुछ परिणाम आते हैं, मुझे लगता है कि यह खुला है, और आयुक्तों का इरादा था कि यह अदालत के लिए खुला होना चाहिए, यह कहने के लिए कि क्या सबूत आयुक्तों के विचार को उचित ठहराते हैं।

इन टिप्पणियों को हैमिल्टन जे द्वारा अमेरिकन थ्रेड कं. वी. टॉयस (²) में समझाया गया था जिसका तात्पर्य यह है कि जिस सामग्री पर उनका निष्कर्ष आधारित था, उसे देकर आयुक्त अदालत को यह निर्धारित करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे कि क्या उस सामग्री पर वे तर्कपूर्ण रूप से उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जिस पर वे पहुंचे थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अपील पर स्पष्ट रूप से पुष्टि की कि न्यायालयों को तथ्य के निष्कर्ष पर यह देखने के अलावा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि क्या कोई सबूत है जो उन्हें उचित ठहराएँ और उचित कानूनी सिद्धांतों को लागू किया गया था।

लॉर्ड क्लर्क में कैलिफोर्निया कॉपर सिंडिकेट बनाम हैरिस (³) ने निम्नलिखित शब्दों में परीक्षण निर्धारित किया है :

" प्रश्न यह निर्धारित किया जाना है-यह योग है लाभ की जिसे मात्र वृद्धि बना दिया गया है किसी सुरक्षा की प्राप्ति से मूल्य, या यह किसी योजना को क्रियान्वित

(1) (1908) 5 टी. सी. 358,374

(2)(1911) 6 टी.सी. 1

(3) (1904) 5 टी. सी. 159,166।

करने में व्यवसाय के संचालन में प्राप्त लाभ है "।

उस स्थिति में ज्ञापन में निर्धारित उद्देश्य संघ का स्पष्ट रूप से एक काल्पनिकता की ओर इशारा किया गया व्यवसाय और कंपनी की वास्तविक प्रक्रिया के तरीका को भी इसी दिशा में निर्देशित किया गया था । शेयरों के लेनदेन की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा लेना और यह भी कि निवेश का मोड़ लेखा-जोखा केवल आकस्मिक नहीं था, बल्कि एक व्यवसाय की आवश्यक विशेषता, अटकलें थी, लेकिन कंपनी के व्यवसाय में नियुक्त साधनों से अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कंपनी एक व्यवसाय चला रही थी।

द लॉर्ड प्रेसीडेंट एक स्कॉटिश मामले में केज़र, इरविन & कं., लिमिटेड बनाम अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त ' आयुक्त के निष्कर्ष के साथ उन आधारों का उल्लेख किया जिन पर अदालत हस्तक्षेप कर सकती है:

" मुझे लगता है कि हमारे पास मनोरंजन करने का अधिकार क्षेत्र है जो कानून में सवाल है, कि क्या बहुमत आयुक्तों को साक्ष्य के आधार पर वारंट किया गया था जैसा उन्होंने किया वैसा निर्धारित करें। एक राज्य के मामले में यह हमेशा सबसे संकीर्ण पर इस न्यायालय के लिए एक खोज की समीक्षा करने के लिए खुला है वास्तव में इस आधार पर कि कोई सबूत नहीं है इसका समर्थन करें।"

लॉर्ड पार्कर में किसान बनाम लेट विलियम कॉटन के न्यासी (2) की कठिनाई का उल्लेख करने के बाद तथ्यात्मक प्रश्न और प्रश्न के बीच अंतर करने के बाद कानून का अवलोकन किया गया:

" जहाँ सभी भौतिक तथ्य पूरी तरह से पाए जाते हैं, और एकमात्र सवाल यह है कि क्या तथ्य ऐसे हैं जो मामले को ठीक से बनाए गए प्रावधानों के अंतर्गत लाएं कुछ वैधानिक अधिनियमों में से, एक प्रश्न केवल कानून है। "

लेकिन कानून के इस कथन को अभिनिर्धारित किया गया था अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त बनाम लिसाघाट (3) में जहां यह माना गया कि

यदि मामला अदालत के समक्ष है निष्कर्ष को "डिग्री का प्रश्न" को तथ्य के प्रश्न रूप में वर्णित किया जा सकता है ।

(1) (1942) 24 टी. सी. 491,501 (3) [1928] ए. सी. 234

(2) (1915) ए. सी. 922,932

अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त बनाम कोरियाई सिंडिकेट लिमिटेड (1) एक ऐसा मामला था जिसमें अधिग्रहण और काम करने के उद्देश्य से एक सिंडिकेट पंजीकृत किया गया था। जिसका उद्देश्य रियायतों को हिसाब में लाना और निवेश करना और ऐसे धन के साथ व्यवहार करना जो तुरंत आवश्यक नहीं है सिंडिकेट ने कोरिया में रियायत के अधिकार का एक हिस्सा हासिल किया और फिर एक समझौते के तहत प्राप्त करने के विचार में इसे "पट्टा" के रूप में वर्णित किया गया है। धन राशि जिसे "रॉयल्टी" कहा जाता है लेकिन जो थी वास्तव में नियोक्ता कंपनी द्वारा किए गए लाभ का प्रतिशत, एक विकास कंपनी को पट्टा सौंपा गया। कुछ धन जो सिंडिकेट द्वारा शेयरों के बदले में प्राप्त कुछ शेयरों की बिक्री से प्राप्त हुए थे मूल रूप से एक बैंक में जमा खनन कंपनी में अधिग्रहित थे । कंपनी की गतिविधियाँ प्रासंगिक अवधि के दौरान बैंक ब्याज और रॉयल्टी प्राप्त करने, अपने शेयरधारकों के बीच लाभांश के रूप में राशि वितरित करने तक सीमित थीं। निर्णय के लिए सवाल यह था कि क्या सिंडिकेट एक व्यवसाय चला रहा था और इसलिए अतिरिक्त लाभ शुल्क के

लिए उत्तरदायी था। इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि वे एक व्यवसाय कर रहे थे।

एटकिंसन एल. जे. ने पी. 204 पर केवल इतना बताया कि क्योंकि एक कंपनी निगमित है, इसलिए इसे यह मानने की आवश्यकता नहीं है कि वह व्यवसाय कर रही है। इसका ज्ञापन केवल यह दर्शाता है कि कंपनी को एक विशेष उद्देश्य के लिए निगमित किया गया था, लेकिन मामले की आसपास की परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि कंपनी एक व्यवसाय कर रही थी ।

ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी बनाम बटर⁽²⁾ निर्णय के लिए सवाल यह था कि क्या एक क्लर्क ने एससीएच. ई. के भीतर आने के लिए एक सार्वजनिक पद संभाला था । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शुद्ध तथ्य के प्रश्नों के आयुक्तों द्वारा किए गए निर्णय को तब तक बाधित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह प्रतीत न हो कि उनके सामने ऐसा कोई सबूत नहीं था जिस पर वे तर्कसंगत व्यक्तियों के रूप में, उस निष्कर्ष पर पहुँच सकें जिस पर वे पहुंचे थे। लॉर्ड एटकिंसन ने कहा:

" इस सदन में मैंने कई बार जिसका विरोध किया है वह यह है कि कानून और तथ्य की अनुपलब्धता के मिश्रित प्रश्न पर निष्कर्ष के लिए सुरक्षित करने का प्रयास है

जो केवल शुद्ध तथ्य के प्रश्नों पर निष्कर्ष से संबंधित है। कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न पर निष्कर्ष को शैलीबद्ध करके इसे प्रभावित करने की कोशिश की जाती है।

लॉर्ड ग्रेनबरी के कथन के अनुसार न्यायालय के लिए प्रश्न यह था कि क्या आयुक्तों द्वारा पाए गए और बताए गए तथ्यों पर क्लर्क ने अधिनियम के अर्थ के भीतर पद संभाला था जो कि कानून का प्रश्न था।

लिसॉट बनाम अंतर्देशीय आयुक्त में निर्णय के प्रश्न और निर्धारिती मूल्यांकन वर्ष में यूनाइटेड किंगडम का सामान्य रूप से निवासी था । लॉर्ड बकमास्टर ने कहा:

" तथ्य के प्रश्नों और कानून के प्रश्नों के बीच अंतर को परिभाषित करना मुश्किल है। यह निश्चित रूप से सच है कि यदि परिस्थितियों द्वारा पाया जाता है विशेष मामले में आयुक्त असमर्थ हैं उनके निवास का गठन करना अनुकूल नहीं हो सकता है , यह कहते हुए कि यह तथ्य का एक निष्कर्ष है क्योंकि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिस पर यह निष्कर्ष निर्भर करता है। लेकिन अगर यात्राओं से संबंधित घटनाएं इस देश में ऐसी प्रकृति है कि वे निवास का गठन करता है, और उनके लंबे समय तक या दोहराए जाने पर पुनरावृत्ति निश्चित रूप से उस परिणाम का उत्पादन करेगी,

फिर मामला स्तर का होना चाहिए; और यहाँ एक मुख्य निवासी या सामान्य निवासी बनने के स्तर लिए अब तक फैली हुई है या नहीं, इसका निर्धारण यहां के आयुक्तों के लिए है और यह न्यायालयों के लिए नहीं है कि क्या वे उसी निष्कर्ष तक पहुँच गए होंगे "।

जोन्स बनाम लीमिंग (2) एक मामला था जहाँ प्रतिवादी तीन अन्य व्यक्तियों के साथ मलय प्रायद्वीप में एक रबर एस्टेट खरीदने का विकल्प प्राप्त किया। वह संपत्ति को दूसरों को लाभ पर बेचा था। आयुक्तों ने पाया कि प्रत्यर्थी ने इसे बदलने के एकमात्र उद्देश्य के साथ तथा फिर से एक लाभ पर इसे धारण करने के लिए संपत्ति अधिग्रहण किया था और कभी भी उनका इरादा नहीं था। यह लेन-देन नहीं होने के लिए आयोजित किया गया था व्यापार की प्रकृति और न ही उससे होने वाले लाभ आय की प्रकृति लेकिन वे संचय थे इसलिए

(1) (1928) 13 टी. सी. 51.1,533, 534.

(1) [1930] ए. सी. 415

पूँजी और एससीएच डी. के मामले VI के तहत कर के अधीन नहीं है। कैमरून बनाम प्रेन्डरगैस्ट (1) निम्नलिखित परीक्षण विस्काउंट मॉम द्वारा निर्धारित किया गया था:

"आयुक्तों द्वारा बताए गए तथ्यों के निष्कर्ष कानून के मामले हैं, और अपील पर उनसे पूछताछ की जा सकती है। यही टिप्पणी दस्तावेजों के निर्माण के बारे में भी सच है।

यदि आयुक्तों का कहना है कि यह सबूत खुला है न्यायालय इस तरह की धारणा से भिन्न होगा।" यदि आयुक्त बताते हैं..... यह साक्ष्य के लिए खुला है अदालत को इस तरह की अधिकार से अलग होना चाहिए।"

बॉमफोर्ड बनाम ओसबोर्न (2) एक खेत मिश्रित खेत के रूप में काम कर रहा था लेकिन एक इकाई के रूप में। निर्णय के लिए सवाल यह था कि क्या मूल्यांकन को एक भाग को खेत के रूप में और दूसरे को नर्सरी के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है। विस्काउंट साइमन ने परीक्षण किया जो शब्द निम्नलिखित है:

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें आयुक्तों, उनके सामने तथ्यों की एक श्रृंखला को साबित या स्वीकार करने के बाद, उससे आगे के निष्कर्ष निकाल सकती है जो स्वयं शुद्ध तथ्य के निष्कर्ष हैं। हालाँकि, ऐसे मामलों में, कानून के दृष्टिकोण से निर्धारण यह है कि

आयुक्त के निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए साक्ष्य कि साबित या स्वीकार किए गए तथ्य प्रदान करते हैं। यह भी माना गया कि यह प्रश्न कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न था।

ड्यू परेंक जे. एच. बीन बनाम डोनकास्टर अम्लगामैटेड कोलियरीज लिमिटेड ⁽³⁾ ने निम्नलिखित को यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण माना कि क्या प्रश्न तथ्यात्मक कानून में से एक है:

" जब तक आयुक्तों ने नहीं पाया कि प्रासंगिक तथ्यों और अपने सामने उचित प्रश्न रखते हुए, वे सही उत्तर देने के लिए आगे बढ़े हैं, इस दृष्टिकोण पर, उन्हें कानून के दृष्टिकोण से गलत कहा जा सकता है। यदि तथ्यों से कोई निष्कर्ष तार्किक रूप से उनके साथ सहमत नहीं है और उनका पालन नहीं करता है, तो किसी को यह कहना होगा कि इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। फिर एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना जिसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है, कानून में त्रुटि करना है।

(1) [1940] 2 सभी ई.आर.35,40 (3)[1944] सभी ई. आर. 279,284

(2) (1941] 2 सभी ई. आर.426,430।

एडवर्ड बनाम बेयरस्टो ⁽¹⁾ में उत्तरदाता ने शीघ्र पुनर्विक्रय और लाभ रखने के उद्देश्य के लिए इसे एक संयुक्त उद्यम पर एक कताई संयंत्र खरीदने

के लिए शुरू किया । सामान्य आयुक्तों ने पाया कि व्यापार की प्रकृति में कोई उद्यम नहीं था, लेकिन अदालत ने माना कि यह तथ्य है, पाया गया कि अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लेन-देन व्यापार की प्रकृति में एक उद्यम था और कि आयुक्त इसके विपरीत निष्कर्ष निकालते हैं गलत था।

लॉर्ड सिमंड्स ने पी. 54 पर अवलोकन किया वह है:

"यह कहना व्यापार की प्रकृति में साहसिकता का तात्पर्य यह है कि इसमें कि कोई लेन-देन है या नहीं है, एक साहसिक कार्य ऐसी विशेषता है जो इस तरह के अंतर करती हैं । लेकिन यह कानून का सवाल है, तथ्य का नहीं, कि वे विशेषताएँ क्या हैं..... "

पी.55 पर लॉर्ड रैंडक्लिफ ने बताया:

" मुझे लगता है कि यह कानून का सवाल है कि आयकर अधिनियम के शब्दों क्या मतलब है जो" व्यापार, निर्माण, जोखिम भरा कार्य या व्यापार की प्रकृति के मामले और इससे होने वाले "मुनाफ़ा या लाभ" दिया जाना है उस मामले के लिए क्या गठन करता है। हमारे पास यहाँ एक कर के प्रभार को शामिल करने वाला वैधानिक वाक्यांश है और यह अदालतों को इसके अर्थ की व्याख्या करने के लिए,

जिस संदर्भ में होता है यह ध्यान में रखते हुए, और सिद्धांतों के लिए जिसे वे आय के अर्थ पर लाते हैं, और फिर पी.57 निम्नलिखित शब्दों में परीक्षण निर्धारित किया:

"जब मामला अदालत के सामने आता है, तो वह उसका कर्तव्य है कि संबंधित कानून को ध्यान में रखते हुए दृढ़ संकल्प की जांच करना उसका कर्तव्य है। यदि मामला कुछ भी कानून से जो प्रत्यक्ष रूप से खराब कानून है और जो लागू होता है निश्चय ही यह स्पष्ट रूप से गलत बिंदु में शामिल है । लेकिन ऐसी कोई गलतफ़हमी सामने नहीं आई, प्रथम दृष्टया हो सकता है कि जो तथ्य मिले हैं वे ऐसे हों कि कोई भी व्यक्ति न्यायिक एवं उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है अपील के निर्धारण तहत संबंधित कानून के बारे में निर्देश दिया जा सकता था ।"

वॉरिंगटन का कथन (2)कूपर बनाम स्टब्स में कि अदालत द्वारा हस्तक्षेप यथोचित है:

(1) [1955] 3 सभी ई. आर. 48.

(2) [1925] 2 के. बी. 753,768,772।

एक बहुत ही स्पष्ट मामले में, जहां आयुक्त या तो बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ।

साक्ष्य जो इसका समर्थन करना चाहिए, अर्थात्, एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जिस पर साक्ष्य के आधार पर कोई भी सक्षम व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है, या स्वयं कानून की दृष्टि से गलत दिशा में जा सकता है। "

और एटकिन एल. जे. के बारे में:

"..... तथ्यों की एक स्थिति हो सकती है जो केवल कानून के एक निष्कर्ष की ओर ले जाता है। पीपी. 56 और 57 में लॉर्ड रैंडविल्फ द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था।

इन अधिकारियों की समीक्षा से पता चलता है कि हालांकि अंग्रेजी निर्णय इस बात की व्यापक परिभाषा के साथ शुरू हुए कि कानून के प्रश्न क्या हैं, अंततः हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय लिया कि "डिग्री का मामला" तथ्य का प्रश्न है और यह भी निर्णय लिया गया है कि आयुक्तों द्वारा कानून की गलत समझ के तहत किसी तथ्य का निष्कर्ष या किसी निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए सबूत की कमी दोनों कानून के प्रश्न हैं।

प्रिवी काउंसिल ने आय कर आयुक्त बनाम लक्ष्मीनारायण बट्टीदास (1) में कहा:

" कानून का कोई सवाल शामिल नहीं था; और न ही यह है, केवल तथ्य के प्रश्न को कानून के प्रश्न में बदलना संभव है यह पूछकर कि क्या कानून के मामले में अधिकारी तथ्य के मामले में सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।"

सेठ सुवालाल छोगलाल बनाम कमिश्नर आय-कर (2) में बोस जे. ने परीक्षण को इस प्रकार बताया:

" एक तथ्य एक तथ्य है जो सिद्ध हो चुका है चाहे कोई भी सबूत हो । ऐसे मामले में कानून का सवाल केवल तभी उठ सकता है जब यह आरोप लगाया जाता है कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिस पर निष्कर्ष आधारित हो या कोई पर्याप्त सामग्री नहीं हों। साक्ष्य की पर्याप्तता को इस अर्थ में समझाया गया था कि क्या आय-कर प्राधिकरण अपने अस्तित्व को इतना अनुकूल मानता है कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति को मामले की परिस्थितियों में इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि यह मौजूद है।

प्रश्न के निर्णय में धीरजलाल गिरधारीलाल बनाम आय-कर आयुक्त, बॉम्बे (3) में यह था कि क्या कोई अविभाजित हिंदू परिवार व्यापार शेयर में कर रहा था और यह माना गया कि यह तथ्य का सवाल था,

(1)[1937]5 आई.टी. आर. 170,179. (3) [1954] 26 आई. टी.

आर 736

(2) 1949] 17 आई. टी. आर. 269,277

लेकिन यदि अपीलीय न्यायाधिकरण उन सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का निर्णय करता है जो जांच के लिए अप्रासंगिक हैं या आंशिक रूप से प्रासंगिक और आंशिक रूप से अप्रासंगिक हैं या आंशिक रूप से अनुमानों पर अपने निर्णय को आधारित करते हैं तो ऐसी स्थिति में

कानून का एक मुद्दा उत्पन्न होता है, जिसकी अदालत द्वारा समीक्षा की जाएगी और न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निष्कर्ष को दूषित कर दिया जाएगा।

अधिकारियों का परिणाम यह है कि तथ्यों से निष्कर्ष तथ्य या कानून का सवाल होगा क्योंकि निर्धारण के लिए बिंदु शुद्ध तथ्य या कानून और तथ्य का एक मिश्रित सवाल है और इसका समर्थन करने के लिए या तथ्य का निष्कर्ष सबूत के बिना आधारित है, यदि प्रासंगिक और अप्रासंगिक मामले अनुपलब्ध नहीं हैं।

तथ्य के प्रश्नों और कानून के प्रश्नों को विभाजित करने वाली सीमा की सीमाएँ इस न्यायालय द्वारा मीनाक्षी मिल्स, मद्रुरै बनाम आय-कर, मद्रास (1) में निर्धारित की गई थीं। जहां निर्णय के लिए प्रश्न यह था कि क्या कुछ लाभ किए गए हैं और इसमें दिखाए गए कि कुछ मध्यस्थों के नाम वास्तव में लाभ थे। लेन-देन के क्रम और लेन-देन की सीमा और मध्यस्थों की स्थिति और वास्तव में निर्धारिती या मध्यस्थों द्वारा अर्जित किया गया। सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मध्यस्थों को अपीलार्थी द्वारा लाभ की वास्तविक राशि को छिपाने के लिए अस्तित्व में लाया गया था और उनके नाम पर बिक्री नकली और काल्पनिक थी और वास्तव में निर्धारिती द्वारा लाभ अर्जित किया गया था। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण उस निर्णय

के विभिन्न अंशों में पाया जाता है। पी. 701 जे. वेंकटरामा अय्यर ने बताया कि तथ्य के प्रश्न अदालत द्वारा समीक्षा के लिए तब तक खुले नहीं हैं जब तक कि वे किसी भी साक्ष्य द्वारा असमर्थित या विकृत न हों। पी. 706 में यह देखा गया:

" तथ्य और कानून के प्रश्नों द्वारा क्रमशः कब्जा किए गए क्षेत्रों के बीच, एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें ये दोनों प्रश्न एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहने के लिए, यह एक दूसरे के भीतर अंतःक्षेत्र बनाते हैं। उस क्षेत्र में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्नों के रूप में जाना जाता है। इन प्रश्नों में सबसे पहले तथ्यों का पता लगाना शामिल है प्रस्तुत साक्ष्य और फिर उचित आवेदन पर पक्षों के

(1) [1956] एससीआर 691।

अधिकारों का निर्धारण तथ्यों के लिए कानून के सिद्धांतों का पता लगाया गया।"

इस प्रकार कानून का सारांश पी. 720 में दिया गया था:

(1) जब संकल्प का बिंदु शुद्ध होता है, कानून का प्रश्न जैसे कि किसी कानून या स्वामित्व के दस्तावेज़ का

निर्माण, न्यायाधिकरण का निर्णय धारा 66 (1) के अदालत को संदर्भित करने के लिए खुला है

(2) जब संकल्प का बिंदु मिश्रित होता है, कानून और तथ्य का सवाल जबकि पाए गए तथ्यों पर न्यायाधिकरण का निष्कर्ष अंतिम है, उस निष्कर्ष के कानूनी प्रभाव के बारे में उसका निर्णय कानून का सवाल है जिसकी अदालत द्वारा समीक्षा की जा सकती है।

(3) तथ्य के प्रश्न पर एक निष्कर्ष खुला है, धारा 66 (1) के अन्तर्गत हमला यदि नहीं है कानून के रूप में त्रुटिपूर्ण है यदि इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है ।

(4) जब निष्कर्ष एक तथ्य है, तो तथ्य यह है कि यह अपने आप में अन्य बुनियादी तथ्यों से एक अनुमान है जो एक तथ्य के रूप में इसके चरित्र को नहीं बदलेगा।

तत्काल मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने अपीलीय आदेश ने आकलन 1943-44 से 1948-49 के वर्षों में निर्धारिती कंपनी द्वारा किए गए लाभ की राशि निर्धारित की है। इसने निर्धारिती द्वारा पहले एक व्यापारी होने और फिर एक निवेशक होने का दावा करने में असंगत स्थिति का भी उल्लेख किया है जो न्यायाधिकरण के अनुसार इस तथ्य के कारण था कि वह पिछले वर्ष में नुकसान उठा रहा था और जब एक निवेशक होने का दावा किया गया था तो उसने लाभ कमाना शुरू कर दिया था। लेकिन

जिन दो बुनियादी तथ्यों पर न्यायाधिकरण ने अपने निष्कर्षों को आधारित किया है, वे हैं:

(1) ज्ञापन में निर्धारित वस्तुएँ निर्धारिती कंपनी का संगठन;

(2) निर्धारिती का पिछला दावा इस बात पर ध्यान दें कि यह निवेश में एक व्यापारी था और केवल एक निवेशक नहीं ।

अधिवक्ता के लिए निर्धारिती के निर्णय पर निर्भर करता है किशन प्रसाद एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आय कर आयुक्त, पंजाब (1) जहाँ इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि लेन-देन कंपनी की शक्तियों के भीतर है या नहीं, इस बारे में सर्कम रुख का लेन-देन की प्रकृति या इस प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि क्या उनसे उत्पन्न होने वाले लाभ पूंजी या राजस्व आय हैं और इसलिए यह तर्क दिया गया है कि न्यायाधिकरण ने

(1) [1955] 27 आई. टी. आर. 49. एम 2 एससी/61-5

एक अप्रासंगिक परिस्थिति पर भरोसा किया है।

अधिवक्ता के लिए दूसरी ओर राजस्व में निर्णय को संदर्भित करता है लक्ष्मीनारायण राम गोपाल बनाम हैदराबाद सरकार (1) जहाँ एक निगमित कंपनी के उद्देश्य को निर्णायक नहीं बल्कि इसकी गतिविधियों की प्रकृति और दायरे को निर्धारित करने का उद्देश्य प्रासंगिक माना गया । केवल इसलिए कंपनी के पास है कि इसका उद्देश्य शेयरों में निवेश करना नहीं है। यदि अन्य परिस्थितियाँ साबित होती हैं तो यह एक प्रासंगिक स्थिति हो

सकती है। प्रकृति निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए विचार ऐसी सामग्री पर जिस पर निर्धारिती कंपनी निर्भर थी, अपने मामले के समर्थन में कि यह केवल एक निवेशक था और एक व्यापारी पर विचार नहीं करना होगा जब कानून के सुझाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है।

तथ्य और कानून का प्रश्न के व्यवसाय की विशेषताएँ क्या हैं या किसी निवेशक के शेयरों का लेन-देन एक मिश्रित सौदा है। तथ्य और अधिकरण का कानूनी प्रभाव क्या है परिणामस्वरूप निर्धारिती को व्यापारी या निवेशक कहा जा सकता है, यह अपने आप में कानून का सवाल है।

कानून के प्रश्न जो न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न होते हैं इस प्रकार हैं:

(1) क्या अभिलेख पर कोई सामग्री है आयकर अधिकारी के निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कि निर्धारिती कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों में एक व्यापारी थी और मूल्यांकन वर्ष के दौरान अचल संपत्ति के सवाल में?

(2) क्या इससे होने वाले लाभ और हानि शेयरों, प्रतिभूतियों और अचल संपत्तियों की बिक्री निर्धारिती कंपनी पर व्यावसायिक लाभ के रूप में कर लगाया जा सकता है?

इसलिए हम इस अपील को स्वीकार करेंगे, इसे अलग रखेंगे और उपरोक्त दो प्रश्नों पर उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण को एक मामला बताने का निर्देश दिया अपीलकर्ता अब तक की कार्यवाही इसकी लागत

इस न्यायालय और उच्च न्यायालय में करेगा आगे का खर्चा पर उच्च न्यायालय का विवेक पर होगा।

अपील की अनुमति दी गई। मामला प्रेषित किया गया।

(1) [1955] 1 एस. सी. आर. 393 (1954) 25 आई. टी. आर. 449।

ये टिप्पणियां किसी भी तरह से प्रतिवादी की मदद नहीं करती हैं और न ही वे सेठ गुरुमुख सिंह के मामले (1) में निर्धारित नियमों के विपरीत कोई नियम निर्धारित करती हैं।

इन कारणों से हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित प्रश्न का उत्तर देने में त्रुटि हुई।

तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को खारिज कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय को भेजे गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। अपीलार्थी इस न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में अपने खर्चों का हकदार होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

पीयूष चौधरी

विशिष्ट न्यायाधीश

अनु. जाति / जनजाति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पियूष चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा